सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

डा. पी. सी. अलेक्जेंडर

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२२ अक्तूबर १९९९

माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

१. महाराष्ट्र विधानसभा के हाल में हुए आम निर्वाचन के बाद, राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. मैं विधानसभा के नवविर्वाचित सदस्यों और नये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करने पर मैं राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूँ.

२. जम्मू-काश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़े समय के भीतर खदेड़ बाहर करने में हमारी सशस्त्र सेना ने जो अतुलनीय वीरता का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है. अपने सैन्यबल के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ. महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के जिन जाँबाज जवानों और अधिकारियों के बलिदान से राष्ट्र को यह सफलता मिली है उनका यह राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा.

३. आगामी वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण योजनायें शुरू करने या पुरजोर जारी रखने का राज्य सरकार का इरादा है. वह मैं अब आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ.

४. सरकार स्वच्छ, पारदर्शी और लक्ष्यपूर्ति की दिशा में ले जानेवाला प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है, जो कि

समाज के उपेक्षित तथा दुर्बल घटकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियों के हित में कार्य करेगा. महाराष्ट्र को अपना पूर्व गौरव पुनःहासिल करने के लिये उच्च प्राथमिकता दी जायेगी.

५. कृषि विकास को सर्वाधिक महत्त्व देने का और कृषि व्यवसाय लाभदायी साबित हो ऐसी व्यवस्था करने का राज्य सरकार का इरादा है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बंजर और परती भूमि तथा खार भूमियों के विकासकार्य और मृदा तथा जल संरक्षण उपायों से, कृषि भूमि के कटाव को रोकने जैसे कार्य को गति प्रदान की जाएगी. किसानों के हित के लिए कृषि बीमा योजना अधिक प्रभावी बनाने की हमारी इच्छा है. किसानों को बेहतर किस्म के बीज और खाद समयपर उपलब्ध कराने के लिये संबंधित ढांचे में आवश्यक सुधार किया जायेगा. रोजगार गारंटी योजना के तहत् फलोत्पादन विकास योजना और जवाहर कूँआ योजना का राज्य में कृषि विकास के प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया जायेगा.

६. सरकार किसानों को सही और अद्यतन भू-अभिलेख देने की दिशा में कार्य करेगी. यह भू-धारकों खासकर छोटे भू-धारकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और इससे जमीन संबंधी मुकदमें भी कम होंगे.

७. राज्य सरकार राज्य के सभी प्रदेशों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने और कमान क्षेत्र विकास पर विशेष ध्यान देगी. सिंचाई

की टपकन और छिड़काव की आधुनिक तकनीक को लोकप्रिय बनाया जायेगा. बच्छावत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कृष्णा घाटी परियोजना समय पर पूरी करने का प्रयास किया जायेगा. विदर्भ सिंचाई निगम, मराठवाडा गोदावरी सिंचाई निगम, तापी सिंचाई निगम और कोंकण सिंचाई निगम की परियोजनाओं को भी गति प्रदान की जायेगी. इस परियोजना से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. राज्य सरकार का भरसक प्रयत्न होगा कि किसानों को सुनिश्चित रूप से निर्बाधित और स्थायी विद्युत आपूर्ति होती रहे.

८. सरकार, प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को अत्यधिक महत्त्व देगी. माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायाभिमुख करने और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के प्रयास भी किये जायेंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा खानाबदोश जनजाति और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखकर उस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायेगा. राज्य सरकार का समग्र उद्देश्य शिक्षा को रोजगार परक बनाना होगा, ताकि राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके. इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उद्योग संबंधी कौशल्य के विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में सुधार करने के प्रयास किये जायेंगे. विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाएगा.

९. नई सरकार, सबसे पहले समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने पर ध्यान देगी. जल्द से जल्द पूरे समाज

को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जायेंगे. सार्वत्रिक टीकाकरण और पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हाथ में लेकर बालमृत्यु दर कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. एड्स जैसी भयानक बीमारी को नष्ट करने के लिए कारगर उपाय किये जाएँगे.

१०. समाज का स्वास्थ्य सुरक्षित जलआपूर्ति पर निर्भर होता है, इस बात को ध्यान में रखकर, सरकार आगामी पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्रों समेत राज्य की सभी जनता को स्वच्छ जलआपूर्ति करेगी.

११. देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है. शहरों में बसी जनता की आवास और नागरी सुविधा संबंधी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं में किये जानेवाले निवेश में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया जाएगा. झोपडपट्टीवासियों का जीवनमान सुधारने के लिए प्राथमिकतापूर्वक प्रयास किया जाएगा. शहरों और औद्योगिक बस्तियों में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है, इस समस्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ठोस उपाय करेगी.

१२. समाज की गरीब जनता मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहती है. इस दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करने के लिए सर्वांगीण प्रयास किये जाएँगे.

१३. पर्यटन उद्योग के अंतर्गत सुविधा और प्रबंध में निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी.

इसके अलावा क्रीड़ा और युवा कल्याण को राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी.

१४. औद्योगिकरण में महाराष्ट्र का अग्रणी स्थान बनाए रखने के लिए और राज्य में सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये जायेंगे. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने के लिए सरकार प्राथमिकता देगी.

१५. श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में सुधार करने के उपाय किये जाएँगे. बाल मजदूरों का शोषण रोकने के लिए योजना कार्यान्वित की जाएगी.

१६. राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा खानाबदोश जनजातियों के कल्याण पर प्राथमिकतापूर्वक ध्यान देगी. जनजाति उपयोजना और विशेष घटक योजनाओं का सक्रिय और कड़ाई से कार्यान्वयन करके इन घटकों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के भरपूर अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे.

१७. निराश्रितों की संजय गांधी निराधार योजना में सुधार करने का सरकार का इरादा है.

१८. राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने और आम जनता को सुरक्षित लगे तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा न पहुंचे ऐसा माहौल तैयार करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

१९. राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुनःस्थापित करने का इस धर्मनिरपेक्ष सरकार का इरादा है. अल्पसंख्यक समाज में सुरक्षितता और अपनेपन की भावना जागृत हो इस दृष्टि से उचित नीतियों पर सरकार पहल करेगी. अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक प्रगति होने के लिए, सरकार आवश्यक उपायों का सुझाव देने हेतु एक एजेंसी तय करेगी.

२०. कुछ अरसे पहले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के जो प्रशासकीय अधिकार हटा लिये गये थे वह उन संस्थाओं को पुनः बहाल किये जाएँगे. राज्य के आर्थिक विकास में सहकारिता आंदोलन की अहम भूमिका रही है, इस बात को ध्यान में रखकर उनकी स्वायतत्ता बरकरार रखने और उनमें नव चेतना फूँकने का भरसक प्रयास किया जाएगा.

२१. इस दशक के आरंभ में राज्य सरकार द्वारा अपनायी गई महिला नीति का कार्यान्वयन अधिक उत्साह के साथ किया जाएगा. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

२२. विदर्भ, मराठवाडा और कोंकण विकास का अनुशेष पूरा करके इन्हें राज्य के विकसित प्रदेश के बराबर लाने के प्रति सरकार वचनबद्ध है.

२३. जनता की बढ़ी हुई आशा आकांक्षा पूरी करने की दृष्टि से विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करना जरूरी है. आर्थिक कठिनाई, खास तौर से पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़े हुए आर्थिक बोझ और १९९५ के बाद बढ़े कर्ज और दायित्व को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ही राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा

करेगी और एक श्वेतपत्रिका पेश करेगी. सरकार विकासेतर खर्च घटाने और कर का आधार बढ़ाकर, करविषयक कानून का सरलीकरण करके तथा कराधान पद्धति में सूसूत्रता लाकर राजस्व में वृद्धि करने का उपाय करेगी. इससे राज्य की कर संबंधी आय में बढोत्तरी होगी और उसका ऱ्हास कम होने में मदद मिलेगी. राज्य की वर्तमान बिकट आर्थिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि को देखते हुए, सरकारी खर्च में कटौती करना, फिजूलखर्ची को रोकना और आर्थिक अनुशासन राज्य सरकार के आर्थिक प्रबंध के त्रिसूत्र होंगे.

२४. लंबे अरसे से चले आ रहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मेरी सरकार सभी प्रयास करेगी.

२५. माननीय सदस्यों, इस सत्र में आपको अनुपूरक माँगों और अत्यावश्यक सरकारी तथा गैर-सरकारी कामकाज पर विचार-विमर्श करना है. इस विचार-विमर्श में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ.

२६. लोकतांत्रिक मोर्चे में शामिल घटकदलों के चुनाव घोषणापत्र पर आधारित न्यूनतम समान कार्यक्रम को राज्य सरकार अमल में लायेगी. मुझे विश्वास है कि, मतदाताओं द्वारा दिये गए जनादेश के अनुसार नई सरकार अपना काम तत्परतापूर्वक और जिम्मेदारी से निभा सके, इसके लिए विधानमंडल के सभी सदस्य मनःपूर्वक सहायता और सहयोग देंगे. मैं पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ.

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई